

सं.ओ.यव./सोनीपत/16-83/59409.—बंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं हरियाणा राज्य विजली बोर्ड, घण्डीगढ़ के श्रमिक श्री वेद पाल तथा उसके प्रवन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को ध्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, अंग्रेजीक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की धारा 10 (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-अम-70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.एस.ओ. (ई) श्रम 70/13648, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे गुस्सेगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायिनीय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों द्वारा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सम्बन्धित मामला है:—

क्षया श्री वेद पाल की सेवाओं का समाप्त न्यायोचित हथा टीक है ? यदि नहीं, तो वह विस राहत का हवदार है ?

सं.श्रो.वि./सोनीपत्त/16-8-3/59416.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं हरियाणा राज्य विजली बोर्ड, चण्डीगढ़ के श्रमिक श्री ओमप्रकाश राठी तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई आंतर्गिक विवाद है;

और चंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इस लिए, अब श्रौद्धोगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राजपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम-70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए. एस.ओ. (ई) दम 70/13648, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उसरें सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है।

क्या श्री श्रोम प्रकाश राठी की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा धीरक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं. अ.वि./सोनीपत/16-83/59423.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं हरियाणा राज्य विजली बोर्ड, चण्डीगढ़ के श्रमिक श्री राजेन्द्र सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम 70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.एस.ओ. (ई) श्रम-70/13648, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री राजेन्द्र सिंह को सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं.ओ.वि.-सोनीपत/16-83/59430.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि गै. हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, चण्डीगढ़ के श्रमिक श्री धर्मबीर तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई आद्योगिक विवाद है;

और चंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम-70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.एस.ओ. (ई) श्रम-70/13648, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा अधिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला हैं या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री धर्मवीर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?